करनाल में लेदर हब बनाया जाए: त्रिलोचन

करनाल। कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने कहा है कि करनाल में इस समय हजारों परिवारों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए लेदर हब की स्थापना करना जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2014 में विधानसभा चुनावों के दौरान करनाल में बड़े लेदर क्लस्टर बनाने की घोषणा की थी लेकिन आठ साल बाद भी इस पर अमल नहीं हो पाया हैं। उल्टे लेदर क्लस्टर करनाल की बजाए रोहतक में बनाया जा रहा हैं।

पिछले आठ साल से मुख्यमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश में कानपुर और आगरा के बाद सबसे ज्यादा लेदर का समान बनाने वाले कारीगर करनाल में रहते हैं। यहां पर लगभग दस हजार छोटे बड़े लेदर के व्यवसायी हैं उनके यहां लगभग पंद्रह से बीस हजार कर्मचारी काम करते हैं। सदर बाजार में घर घर में जूता बनाया जाता हैं। लगभग पचास से साठ हजार लोग लेदर उद्योग पर निर्भर है। पिछले कई दशकों से यह उद्योग असंगठित क्षेत्र में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से करनाल में लेदर उद्योग का क्लस्टर बनाने के साथ लेबोरेटरी बनाने की मांग की हैं।

बीजेपी सरकार ईडी के माध्यम से कर रही है गांधी परिवार को परेशान - लहरी सिंह

करनाल। कांग्रेस जिला कमेटी करनाल द्वारा 22 जुलाई को केंद्र मे बीजेपी सरकार द्वारा गांधी परिवार को ईडी के माध्यम से परेशान किये जाने के खिलाफ सुबह 11 बजे करनाल मानव संघ के बाहर से विरोध मार्च निकाल कर प्रदर्शन किया जायेगा। विरोध मार्च करनाल के मानव संघ के पास करण पार्क से शुरू हो कर कमेटी चौक, सब्जी चौक, करण गेट, पुरानी सब्जी मंडी से होते हुए कमेटी चौक पहुंचेगा। यहां केंद्र सरकार और ईडी का पुतला फूंका जायेगा। यह जानकारी पूर्व विधायक तथा जिला प्रभारी लहरी सिंह ने दी। वह करनाल के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस मे कांग्रेस कार्यकर्ता मीटिंग मे बोल रहे थे। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ईडी का प्रयोग अपने विरोधियो को परेशांन करने के लिए कर रही है। पहले श्री राहुल गांधी को दस दिन तक ईडी ने पूछताछ के बहाने परेशांन किया और अब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को पूछताछ के लिए तलब किया है।

इस अवसर पर पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान, राकेश कांबोज, जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह, डॉ सुनील पं वार, सीनियर कांग्रेस नेता रघुवीर संधु, पंकज पूनिया, कृष्ण बस्ताडा,पार्षद पप्पू लाठर, हरी राम साभा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष उषा तुली, डॉ, गीता, रानी कांबोज, अमर जीत धीमान, धर्म पाल कौशिक, ओम प्रकाश सलूजा, इंद्रजीत सिंह गुराया, राजेश वैद्य, जोगेंद ्चौहान, सतपाल जानी, सुरेंद्र कालखा, जीत राम कश्यप, जोगेंद ्वाल्मीकि, राजेंद्र नम्बरदार,ज्ञान सिंह, बलजीत शर्मा, परम जीत वाल्मीकि, ललित अरोड़ा, राजेंद्र पप्पी, अनिल शर्मा, जागीर सिंह, संदीप बलडी, सुनेहरा वाल्मीकि, गगन मेहता, बीरबल तँवर आदि उपस्थित थे।

सीजेएम जसबीर ने जिला जेल का किया निरीक्षण और जेल लोक अदालत का हुआ आयोजन

करनाल। मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट. एवं.सचिवए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण करनाल सुश्री जसबीर बुधवार को जिला जेल का निरीक्षण किया और बंदियों से बातचीत की। बंदियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यदि उनके पास अपने मामलों की रक्षा के लिए कोई कानूनी सहायता वकील नहीं है तो वे जेल अधीक्षक के माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं, ताकि कानूनी सहायता वकील उनके मामलों में लगे रहे। जेल प्रशासन द्वारा उन्हें दी जा रही सुविधाओं के संबंध में उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है। इस अवसर पर सीजेएम द्वारा जिला कारागार करनाल में जेल लोक अदालत का आयोजन किया। छोटे अपराधों में शामिल 6 अपराधों जैसे कि घोषित अपराधी, चोरी आदि को सीजेएम के समक्ष लाया गया जिनमें से 1 कैदी को उनके कबूलनामे के आधार पर अन्डरगोन किया गया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक अमित भादु, उपाधीक्षक अशोक कम्बोज एवं शैलाक्षी भारद्वाज उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान सीजेएम ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि कैदियों के उपयोग के लिए दैनिक जरूरत की वस्तुओं की समुचित व्यवस्थाएं की जाए ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। सीजेएम ने जेल अधीक्षक को उन मामलों की छानबीन करने का भी निर्देश दिया जहां छोटे-छोटे अपराधों में विचाराधीन कैदी हैं ताकि ऐसे मामलों को अगले महीने होने वाली जेल लोक अदालत में इन विचाराधीन कैदीयों के मामलों को रखा जाए। उन्होंने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए कि आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लेते समय उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। क्योंकि यह उसका संवैधानिक अधिकार है, ताकि निचली अदालत में उसके मामले का उचित रूप से बचाव किया जा सके। उन्होंने जेल अधीक्षक को विशेष रूप से अदालत के समक्ष पेश किए जाने वाले विचाराधीन कैदियों के मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के उनके दायित्वों के बारे में याद दिलाया।

भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाले सिमरनजीत सिंह पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग

करनाल। एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा कि दु:ख की बात है बीजेपी सरकार शहीदों की सोच पर पहरा देती है। करनाल सीएम सिटी आकर खालिस्तानी मुहिम चलाने वाले सिमरनजीत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह को आतंकवादी बताया और 16 जुलाई की एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया की शिकायत पर एसपी करनाल ने एफआईआर दर्ज नही की। शांडिल्य ने आईजी करनाल सतेंद्र गुप्ता को सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ भगत सिंह को आतंकवादी बताने पर फोन पर बात की जिस पर आईजी ने आश्वासन दिया कि वह तुरंत एसपी करनाल को कार्रवाई के आदेश दे रहे हैं।

वीरेश शांडिल्य

आईजी करनाल रेंज

शांडिल्य ने आईजी को भेजे पत्र में कहा कि एसपी गंगा राम पुनिया को 16 जुलाई को सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ ईमेल से व 18 जुलाई को एसपी को आकर शिकायत दे चुके। एसपी ने 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया था। जिस भगत सिंह को 132 करोड़ लोग प्यार करते हैं, भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें देश का हीरो कहते हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में शहीद-ए-आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगी हुई है, ऐसे में भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाला खलिस्तानी जरनैल सिंह भिंडरवाला समर्थक मान पर एफआईआर दर्ज कर जेल में नही डाला गया। यदि तुरंत भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाले सिमरननजीत सिंह मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हुआ तो वो बीजेपी सरकार के शहीदों के प्रति ढुलमुल रवैये के खिलाफ हरियाणा राजभवन पर धरना देने के लिए विवश होंगे ।

वीरेश शांडिल्य ने कहा, राजभवन पर धरना देने से पूर्व व वीरवार को वह हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को मिलेंगे और शिकायत देंगे, फिर भी सिमरनजीत मान पर एफआईआर दर्ज न हुई तो राज भवन पर धरना देंगे।

एमएसपी मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक

हरियाणा के करनाल के गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में संयुक्त किसान मोर्चा की बुधवार को मीटिंग हुई। मीटिंग में केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर बनाई गई कमेटी को संयुक्त किसान मोर्चा ने सिरे से खारिज कर आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी। किसान नेता जोगिंद्र उगराहां, योगेंद्र यादव और रतनमान ने दो टूक कह दिया कि किसानों को कमेटी किसी हाल में मंजूर नहीं। सरकार पिछले दरवाजे से 3 कृषि कानूनों को लाना चाहती है। कमेटी में उन लोगों को शामिल किया जो शुरू से लेकर अंतिम दिन तक कानूनों की वकालत कर रहे थे। सरकार की मंशा को कामयाब होने नहीं देंगे।

पत्रकारों से बातचीत करते किसान नेता जोगिंद्र उगराहा।

पत्रकारों से बातचीत करते किसान नेता योगेंद्र यादव।

किसान एमएसपी पर मांग रहे गारंटी कानून

जोगिंद्र उगराहां ने कहा कि जो प्लान एसकेएम ने बनाया था उसे लागू करने के लिए करनाल में मीटिंग रखी गई थी। केंद्र सरकार ने कमेटी में किन लोगों को लिया जाएगा उसे साफ नहीं किया था। कमेटी किस लिए बनाई गई है, ये भी स्पष्ट नहीं है। किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को दूर रख रही है। जो किसानों को मंजूर नहीं। सरकार ने जो कमेटी बनाई है, उसमें पता नहीं किन-किन लोगों को खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद यूपी में हुए सम्मेलन में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था कि एसकेएम कमेटी में नहीं जाएगा।

कमेटी को लेकर किसानों ने जताया था संदेह

किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर कमेटी बनाने की बात कही थी, उसी वक्त किसानों ने कमेटी बनाने पर संदेह व्यक्त किया था। वह अब सही साबित हो चुका है। सरकार ने कमेटी में उन लोगों को शामिल किया है जो कानूनों की वकालत करते थे। हैरानी की बात यह है कि कमेटी का अध्यक्ष उसे बनाया है, जिसने कानूनों को बनाया था। कमेटी में 3 नेताओं के नाम मांगे हैं। वह कह रहे हैं कि एसकेएम नाम नहीं दे रहा है। जब हमें पता ही नहीं कि कमेटी किस लिए बनाई है। कमेटी एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर है या कुछ और ?

सरकार की कमेटी में आरएसएस और बीजेपी के लोग

उन्होंने आरोप लगाया कि कमेटी में 5 ऐसे लोगों को बैठा दिया जो आरएसएस और बीजेपी के हैं। यह सभी 3 कृषि कानूनों के समर्थक हैं। सरकार पिछले दरवाजे से तीनों कृषि कानूनों को लाने की कोशिश करेगी, इसलिए सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी में जाने और सहयोग का कोई मतलब नहीं है। हम सरकार की कमेटी को खारिज करते हैं और कमेटी का भंडाफोड़ करेंगे। हमें कमेटी नहीं चाहिए। सरकार पहले एक एमएसपी पर कानून बनाने का एग्रीमेंट दे।

7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक होगा जय जवान जय किसान सम्मेलन

उन्होंने कहा कि किसान संगठनों की बैठक में जो निर्णय लिए थे उन्हें हरियाणा में लागू करने की योजना बनी थी। मीटिंग में फैसला हुआ कि 31 तक बकाया मांगों को लेकर सम्मेलन करना, 4 घंटों के लिए चक्का जाम करना।

सात अगस्त से 14 तक हर जिला स्तर पर जय जवान जय किसान सम्मेलन, जिसमें एक्स सर्विसमैन, बेरोजगारों के संगठन शामिल रहेंगे।

उन्होंने कहा कि एसकेएम किसानों के हकों के साथ खड़ा रहेगा। किसानों की जमीन नहीं छीनने देंगे। इसके लिए पांच अगस्त से सभी डीसी को ज्ञापन दिए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा हर मुद्दे पर लड़ेगा। अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए एसकेएम जय जवान जय किसान सम्मेलन आयोजित कर रहा है।

यह 14 हजार करोड़ में बनने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। जिसका पूरे तामझाम के साथ इसी 16 जुलाई को पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन हुआ था। वह पहली बरसात भी नहीं झेल पाया।